

नौमनि ,भारत सरकार के ई-न्यूज़लैटर का 5वां अंक, जुलाई, 2017



भारत सरकार,
पोत परिवहन मंत्रालय,
नौवहन महानिदेशालय,
बीटा बिल्डिंग, 9 वीं मंजिल, आई-थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजूर मार्ग (पूर्व), मुंबई-400 042
फोन: 91-22-25752040/43 ईमेल: dgship-dgs@nic.in वैबसाइट: dgshipping.gov.in

नौमनि, भारत सरकार का ई-न्यूज़लैटर
(नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार का तिमाही ई-न्यूज़लैटर)

संरक्षक:	डॉ. मालिनी वी. शंकर, भाप्रसे, नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार	संपादकीय...
सलाहकार मंडल:	1. श्री अमिताभ कुमार, भारासे, अपर नौवहन महानिदेशक. 2. श्री बी आर शेखर, मुख्य सर्वेक्षक 3. श्री सुरेश कुमार, मुख्यकोत सर्वेक्षक 4. कप्तान केपी जयकुमार, उप नौटिकल सलाहकार	नौवहन को लंबे समय से समाजार्थिक विकास का एक सशक्त उत्प्रेरक माना जाता रहा है। देश में होने वाला व्यापार बाहर की दुनिया से जुड़े बिना उच्च स्तर की कार्य कुशलता, लाभदेयता और एक से दूसरे में नहीं पहुँच सकता। समुद्रीय यातायात पर्यवेक्षण विभाग के रूप में पोत प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें पोत की सुरक्षा की महत्ता निहित होती है। इसके अन्यत कार्यों के साथ-साथ नौमनि ने हाल ही में समुद्रीय सुरक्षा सलाह जारी की है जिसके अनुसार जलयान अदन की खाड़ी (सोमालिया क्षेत्र का तट) में प्रवेश न करें और इस क्षेत्र से दूर ही रहें। किसी को भी इस सुरक्षा सलाह के प्रति कतई लापरवाह नहीं होना चाहिए। पोत प्रचालन की दृष्टि से समुद्रकर्मियों का महत्वर सर्वाधिक होता है इसलिए उनका ठीक तरह से खयाल रखा जाना चाहिए। एमएलसी, 2006 में अधिकारों के सुरक्षोपाय दिए गए हैं और समुद्रकर्मियों की आवश्यकताएं बताई गई हैं। इसी तरह से एमएलसी प्रशिक्षणार्थियों और कैडेटों पर भी लागू होता है। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अंतर्गत दिनांक 01.07.2017 से जीएसटी को लागू किया गया है। नौमनि ने नौवहन जगत में जीएसटी की प्रयोज्यता पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उद्योग को आवश्यकता इस बात की है कि अंतर्राज्यीय लेन-देन हेतु महत्वपूर्ण, 'आपूर्ति का स्थान' की निर्णायक संकल्पना सहित विस्तार से विधि के प्रावधानों का विश्लेषण करे। ई-न्यूज़लैटर में समुद्रीय जानकारीयां प्रदान की जाती हैं। आपको इसे पढ़ने के बाद कैसा लगता है आप हमें बताएं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो। ---गिरधारी लाल सिंह
संपादक :	जी एल सिंह, कन्सुलेंट हेल्प डेस्क	
संपादकीय सहायता :	1. श्रीमती आर. आई. सोलकर, कन्सलेंट 2. श्रीमती वी. आई. शर्मा, कन्सलेंट 3. श्री डी. डी. मंकीकर, कन्सलेंट हेल्प डेस्क	
हिंदी अंक:	पांचवा	
संपादन तथा अनुवाद:	विमलेन्द्र भदौरिया	
टाइपसेटिंग:	श्रीयुत श्रीराम	

अस्वीकरण: इस न्यूज़लैटर में निहित सामग्री मात्र सूचना के प्रयोजन से है। इसमें निहित सामग्री के सटीक होने या फिर अधिप्राप्तिक होने का कोई दावा नहीं है, न इस न्यूज़लैटर में दी गई यहसमें कहीं से समाविष्ट की गई किसी भी जानकारी हेतु किसी व्यक्तिगत संगठन को उत्तोरदायी ही ठहराया जा सकता है।



नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार का वक्तव्यव ...

आवधिक निरीक्षण को किए जाने की आवश्यकता के लिए ध्वज राष्ट्रों की अपेक्षा को समझते हुए नौमनि ने इसकी एफएसआई / पीएससी व्यवस्थाए की समीक्षा की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जलयान समुद्र में चलने लायक स्थिति में हैं तथा उनके पास आवश्यक प्रमाण-पत्र हैं। समीक्षा में इस आवश्यकता पर बल दिया गया कि तय किया गया निरीक्षण किया जाए साथ ही यथावश्यक रूप से अचानक निरीक्षण भी किया जाए। निदेशालय ने यह भी निर्णय लिया है कि उन जलयानों को अगली एफएसआई / सामान्य परीक्षा से छूट दी जाए जिन्होंने तय देशों द्वारा समरूत पीएससी निरीक्षण संतोषजनक रूप से करवा लिए हैं और जिनमें ऐसी कोई कमियां न हों जिनके कारण इन्हें रोका जा सके और कमियां यदि हों भी तो कुल मिलाकर ये पांच से अधिक न हों।

एसटीसीडबल्यू के अंतर्गत प्रकार्य की सक्षमता हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करने की योग्यता वाकई एक महत्वपूर्ण गुण है। परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु तैयारी पाठ्यक्रम किए जाएं। प्रोफेशनल कौशलों, गुणवत्ता प्रदर्शन में अभिवृद्धि लाने की दृष्टि से इस निदेशालय के नए भर्ती हुए / अधिकारियों हेतु एक गैर तकनीकी (प्रशासनिक) प्रशिक्षण आयोजित किया गया। दिनांक 25 जून, 2017 को समुद्रकर्म दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्यातन से किया गया और इसका समापन मंत्रालय में लगाई गई प्रदर्शनी से हुआ, प्रयोजन यह था कि नौवहन की महत्ताय और समुद्रकर्मियों के अनूठे योगदान की ओर ध्यानाकर्षित किया जा सके।

(डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे)

नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार

**माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग, पोत परिवहन, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री
भारत सरकार का नौमनि मुंबई में पदार्पण**

माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग, पोत परिवहन, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री, श्री मनसुख एल. मांडविया, नौमनि के कार्यालय में पधारे। डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे, नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार और श्री अमिताभ कुमार, भारासे, अपर नौवहन महानिदेशक ने उनका स्वांगित किया।



माननीय मंत्री महोदय ने दिनांक 11 मई, 2017 को 1100 बजे नौवहन महानिदेशालय के अधिकारियों और नौवहन उद्योग के हितधारियों के साथ बैठक की। इस बैठक का प्रयोजन यह था कि हितधारियों से यह जाना जाए कि भारतीय नौवहन जगत को किस तरह से और प्रखर बनाया जा सकता है तथा उद्योग से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाए, खासतौर से ऐसे तरीके ईजाद किए जाएं जिनसे भारतीय समुद्रकर्मियों को मिलने वाले रोजगार के अवसर बढ़ें।

नौवहन महानिदेशालय, एलआरआईटी की भूमिका, समुद्रमर्मियों से संबंधित आंकड़े और कामराज पत्तीन एन्नौरर में पोतों की भिड़न्त से संबंधित प्रस्तुततीकरण किए गए । नौवहन महानिदेशालय द्वारा आरंभ किए गए प्रमुख कानूनी सुधारों पर भी माननीय मंत्री महोदय को जानकारी दी गई । प्रस्तुतीकरणों के उपरांत बातचीत का एक सत्र आयोजित किया गया जिसमें मंत्री महोदय ने नौवहन उद्योग के प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए ।



नौ-अधिकरण विधेयक तथा वापोप विधेयक जैसे नए विनियमों को शुरू करने संबंधी नौवहन महानिदेशालय के प्रयासों की माननीय मंत्री महोदय ने प्रशंसा की । टास्कि फोर्स द्वारा की गई संस्तुह्तियों की भी तारीफ की गई और समुद्रीय कामकाज के बारे में जागरूकता लाने हेतु निजी तथा सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया । माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा कि भारतीय नौवहन उद्योग का विकास उनकी प्राथमिकता वाली परियोजना है । उन्होंने ने बल दिया कि समुद्रकर्मि हमारे देश का प्रतिनिधित्वथ दूसरे देशों में जा कर राजदूतों की तरह करते हैं और अगर उनमें कौशल होगा तथा आगे बढ़कर काम करने की ललक होगी तो दुनिया के बाजार में सबसे पहले उन्हीं की पूछ होगी और उनकी उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ेगा ।



माननीय मंत्री महोदय के साथ नौमनि, अपर नौमनि तथा अन्य3

समुद्रकर्मियों / हितधारियों की प्रतिक्रिया :

नौवहन महानिदेशालय, कांजूरमार्ग, मुंबई में 10 अप्रैल को मेरी क्लारस 2 की मौखिक परीक्षा हुई। मेरे विचार से मौखिक परीक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजित की गई। पूछे गए सभी प्रश्न पोत पर आवश्यक समुद्रीय इंजीनियरिंग और संकल्पनाओं के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित थे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो पाठ्यक्रम से बाहर का रहा हो। परीक्षक ने मेरा उत्साहवर्धन किया और सोच विचार कर उत्तर देने के लिए मुझे पर्याप्त समय दिया। परीक्षा लेने के तरीके से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।

स्त्री भाग्यतस्त्री ओगाले, टिकट नं. 213113

डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे, नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे, विशेष सचिव के स्तर पर उसी जगह क्रमोन्नत करने का अनुमोदन प्रदान किया। वर्तमान में डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे, के पास नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार, मुंबई (भारतीय समुद्रीय प्रशासक) का कार्यभार है।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पहले ही केन्द्र में सचिव / सचिव स्तर के पद पर नियुक्ति हेतु डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे, (महाराष्ट्र 1984) का नाम अनुमोदित कर दिया है।

संपादक मंडल नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार और समूचे नौवहन जगत की ओर से डॉ. मालिनी वि. शंकर को विशेष सचिव, भारत सरकार के पद पर पदोन्नत होने के परिणाम स्वरूप बधाईयां और शुभकामनाएं देता है।

-गिरधारी लाल सिंह, संपादक और उनका संपादक मंडल

अदन की खाड़ी (सोमालिया क्षेत्र आदि के तट) के पार जाते पोत / जलयान – समुद्रीय सुरक्षा सलाह



Image Credit: European Union Naval Force, Somalia

नौमनि ने दिनांक 06.04.2017 के नॉटिकल अनुभाग से जारी समुद्रीय लूटपाट संबंधी परिपत्र सं. 1/2017 के माध्यम से यह सलाह / चेतावनी पाल जलयानों और मात्स्यिकी जलयानों सहित सभी भारतीय पोतों के स्वामियों / प्रचालकों और मास्टमरों को दी गई है वे इस क्षेत्र में न जाएं और अपने जलयानों को इस क्षेत्र से दूर रखें और यथासंभव रूप से कम से कम तट से न्यूनतम 200 नॉटिकल मील से अधिक की दूरी बनाए रखें।

जो इन अनुदेशों का उल्लंघन कर अपने जलयान इस समुद्रों में चलाएंगे तो जोखिम के लिए भी वे ही जिम्मेदार होंगे। विभिन्न कोरियाई नौसेना पोतों, यूके, समुद्रीय व्यापार प्रचालकों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय ब्यूरो ने बताया है कि लूटपाट में एमएसवी का अपहरण फिरौती वसूल करने के लिए किया जा रहा है।

समुद्रकर्मियों / हितधारियों की प्रतिक्रिया :

यह बहुत ही मददगार और प्रयोग करने में आसान है। इससे समय की काफी बचत होती है।

- 1) परीक्षा की बुकिंग
- 2) हाल टिकट और परीक्षा पत्रक आसानी से मिलना

साहिल कटारिया टिकट नं. 266911

कार्य बल समिति भारतीय समुद्रकर्मियों का बढ़ता नियोजन :

नौवहन और लॉजिस्टिंग उद्योग बढ़ोतरी के लिए सन्नध है, इसमें बहुत ही शानदार कैरियर और नियोजन के अवसर निहित हैं। विश्वग में भारतीय समुद्रकर्मियों के नियोजन में बढ़ोतरी की रूपरेखा और कार्य पद्धति संबंधी योजना को तैयार किए जाने की दृष्टि से हितधारियों (इन्साय, मासा, फोसमा, इक्सा, नूसी, एमयूआई, एमएससी आदि) के साथ दिनांक 31.03.2017 को विचार-विमर्श के आधार पर निदेशालय ने निर्णय लिया कि मुद्दों की जांच करने के लिए नौमनि के अध्यक्षता के अंतर्गत एक कार्य बल समिति का गठन किया जाए।

जून, 2017 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान दिनांक 06.04.2017 और 27.04.2017 को दो बैठकें आयोजित की गईं। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त 6 मुद्दों में निर्णय लिया : 1. कार्यशाला प्रशिक्षण तथा संचार कौशलों सहित दिए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार;

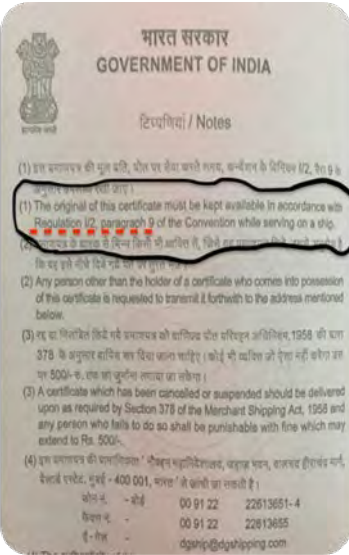
2. इसमें पक्षधरों तथा विमान पक्षधरों में भारतीय समुद्रकर्मियों हेतु ई-माइग्रेन्टन कार्यक्रम का कार्यान्वयन;

3. भारतीय अधिकारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार ;

4. भारतीय समुद्रकर्मियों को इस लायक बनाना कि वे यूरोप, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, रूस आदि देशों के पोतों पर जाकर यथास्थिति कार्य कर सकें न कि महज वीजा पा के बैठ जाएं। समिति में इस बात पर विचार किया गया कि भारतीय समुद्रकर्मियों की सक्षमता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के क्या तरीके हों।

आशा है कि समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

सीओसी पृष्ठों कन – विनियम 1/2. परिच्छेद 11:



नौमनि ने समुद्रीय वाणिज्यस विभागों को दिनांक 24.04.2017 के नॉटिकल / इंजीनियरिंग परिपत्र सं. 1/2017 के माध्यम से निदेश दिया है कि जिन सक्षमता प्रमाण पत्रों यानी सीओसी को पुनः मान्यता प्रदान की गई है जिनके अगले पृष्ठ पर 'विनियम 1/2, कन्वेंशन का परिच्छेद 9' की टिप्पणी के साथ एसटीसीडबल्यू, 1978 कन्वेंकशन के 2010 वाले संशोधनों तक अद्यतनीकृत सक्षमता प्रमाण पत्रों का पृष्ठों कन कर मोहर लगाई जाएगी जिसके अंतर्गत सीओसी पुस्तिका के अतिरिक्त पृष्ठों में, 'पोत पर कार्य करते समय कन्वेंकशन के विनियम 1/2, परिच्छेद 11 के अनुसरण में इस प्रमाण की मूल प्रति आवश्यक रूप से उपलब्ध रखी जाएगी', लिखा होगा।

जिन समुद्रकर्मियों के पास 2010 संशोधनों तक अद्यतनीकृत सक्षमता प्रमाण पत्र हैं वे अपनी सुविधानुसार अपने सक्षमता प्रमाण पत्र पर तदनुसार मोहर लगवाने के लिए अपने निकटतम समुद्री वाणिज्य विभाग में जा सकते हैं।

पत्त न राष्ट्र नियंत्रण निरीक्षणों के दौरान एसटीसीडबल्यू में 2010 के संशोधनों की अनुपालना वाले भारतीय सक्षमता प्रमाण पत्रों से संबंधित मुद्दों की रोकथाम करने के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र के अगले पृष्ठ की टिप्पणियों को निम्नोक्तन रूप से पढ़ा जाए :

“पोत पर कार्य के दौरान इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति कन्वेंकशन के विनियम 1/2, परिच्छेद 11 के अनुसरण में अवश्यो रखी जाए”

तैयारी पाठ्यक्रम - मूल्यांकन हेतु आवश्यकता

सक्षम प्राधिकारी ने इस बात पर बल दिया है कि तैयारी पाठ्यक्रम पूरा होने के प्रमाण पत्रों को जारी किए जाने से पहले अभ्यर्थियों का लिखित और मौखिक मूल्यांकन किया जाए। समुद्री संस्थाओं को भी दिनांक 02.05.2017 के इंजीनियरिंग परिपत्र सं. 138/2017 के माध्यम से सलाह दी गई कि वे दो वर्ष तक सभी परीक्षाओं के अभिलेख अपने पास रखें। आवधिक निरीक्षणों के दौरान इनका सत्यापन किया जाएगा। (उद्योग से प्राप्त प्रतिक्रिया और एमईओ क्लारस 1 तथा एमईओ क्लारस 2 परीक्षाओं के परिणामों के उपलब्ध डाटा से पता चलता है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है)।



इस पाठ्यक्रम का मंतव्य यह है कि अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए तैयार किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अभ्यर्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएं।

समुद्रकर्म / हितधारी की प्रतिक्रिया :

एमईओ की लिखित और मौखिक परीक्षाओं के लिए सीट बुक कराने के साथ-साथ शुल्क जमा कराना भी आसान है, इसमें न तो कोई जोखिम है न कोई झंझट। हम अपना परिणाम ई-गवर्नेंस साइट पर भी देख सकते हैं।

राजेन्द्रा सिंह बुटोला, टिकट नं. 759069

नौमनि द्वारा सवावि, हल्दिया के नए कार्यालय का उद्घाटन

डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार ने दिनांक 8 मई, 2017 को श्री जी सेन्तिलवेल, उपाध्यक्ष कोलकाता पत्तईन न्यादस, श्री एस. के. सिन्हाध, प्रधान अधिकारी समुद्री वाणिज्य विभाग, कोलकाता और उनकी टीम की उपस्थिति में समुद्री वाणिज्यल विभाग, हल्दिया के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया।



नौमनि ने नौवहन जगत तथा अन्यक संबद्ध उद्योगों तक सेवाओं को पहुँचाने के लिए हल्दिया में प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, कोलकाता का एक अधीनस्थ कार्यालय दिनांक 07.07.2003 को खोला था। तब से लेकर इसका कामकाज कोलकाता पत्त न न्याइस – हल्दिया डॉक कम्पलेक्स के प्रचालन भवन द्वारा दिए गए एक कमरे में होता आ रहा है।

यह कार्यालय भवन चिरंजीवपुर हल्दिया में 2000 वर्गमीटर के एक प्लॉट पर बनाया गया है जिसका पट्टा 30 साल के लिए कोलकाता पत्तलन न्यायस्थल द्वारा नौमनि के नाम लिखा गया है। केलोनिवि ने वर्ष 2010 में निर्माण कार्य आरंभ किया और इसके निर्माण तथा बिजली संबंधी कार्यों के पूरे होने के पश्चात् 02.01.2017 को सवावि, हल्दिया द्वारा यह भवन अपने कब्जे में ले लिया गया।

प्रधान अधिकारी सवावि, कोलकाता और उनकी टीम ने सवावि, हल्दिया के भवन से लगी भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य आरंभ किया। इस अभियान का शुभारंभ नौमनि की उपस्थिति में किया गया। नौमनि ने इस पर्यावरण अनुकूल पहल की प्रशंसा की और सभी का आह्वान किया कि वे अभियान में शामिल होकर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें।



नए कार्यालय भवन में आने के उपरांत सवावि, हल्दिया के संपर्क विवरण निम्नांकनुसार हैं :



कार्यालय	समुद्री वाणिज्य विभाग, चिरंजीवपुर (बीएसएनएल कार्यालय भवन के सामने) हल्दिया-721604, पूर्वी मेदनीपुर, बंगाल । फोन / फैक्स 03224-253986, ई-मेल आईडी : mmdhaldia@gmail.com
प्रभारी सर्वेक्षक	अनिरुद्ध चक्कीड फोन नं. - 03224-297032 (मो.) 09820384521, ई-मेल आईडी : haldia-sicmmd@gov.in
नॉटिकल सर्वेक्षक	कप्तान सव्य साची मुखोपाध्याय (मो.) 09830023923, ई-मेल आईडी: capt.sabyasachi@gmail.com

समुद्रकर्मी / हितधारी की प्रतिक्रिया :

मुझे हैरानी हो रही है कि 10 दिन के भीतर मेरा बदला हुआ सीडीसी मुझे मिल भी गया । इस महती सेवा के लिए मैं नाविकपाल कोलकाता का हृदय से आभारी हूँ । मुझे सवावि, कोलकाता पर गर्व है । धन्यसवाद
कपिल चौधरी टिकट नं. 197944

मिनीकाँय द्वीप समूह के निवासियों के लिए नौमनि द्वारा कल्याण उपायों पर विचार

नौवहन महानिदेशक ने लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वाले मिनीकाँय द्वीप मूल के निवासी उन अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अपेक्षा घटाकर आठवीं पास कर दी है जो जीपी रेटिंग कोर्स हेतु समुद्र पूर्व 6 मास के प्रशिक्षण में प्रवेश लेना चाहें और समुद्रीय खानपान में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (सीसीएमसी) और सीडीसी प्राप्त करना चाहें।



यह नौमनि के आदेश दिनांक 09.05.2017 को जारी नौमनि आदेश सं. I/2017 में निहित निश्चित शर्तों पर निर्भर होगी।

समुद्रकर्म / हितधारी की प्रतिक्रिया :

बहुत ही बढ़िया और हर तरह से सदैव सहायता हेतु तत्पर

बालू ए. अय्यर । टिकट नं. 612621

व्यापक निरीक्षण कार्यक्रम : बाध्यकारिताओं पर खरे उतरें

(1) नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सीआईपी मार्गदर्शन हेतु नौमनि आदेश सं. 23/2014 जारी किया गया था। आज तक, कई संस्थानों ने सीआईपी नहीं करवाया है। भारतीय समुद्रीय प्रशासन ने सीआईपी न करवाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों के इस ढीले रवैये को गंभीरता से लिया है और निदेश दिया है कि समुद्र पूर्व पाठ्यक्रमों को आयोजित करने वाले जो प्रशिक्षण संस्था 31 जुलाई, 2017 तक मार्गदर्शी सिद्धांतों पर खरे नहीं उतरते तो पाठ्यक्रमों में उनकी भर्ती की क्षमता को अगस्त, 2017 से 10 प्रतिशत घटा दिया जाएगा।

(2) दिनांक 17.11.2016 के माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में तथा नौमनि अनुमोदित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में दिए जा रहे शिक्षण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को दिनांक 30.05.2017 के नौमनि आदेश सं. 3/2017 के माध्यम से निदेश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित समुद्री वाणिज्य विभागों के माध्यम से सीआईपी करवाएं। अगर वे चाहें तो यह कार्य आरओ के माध्यम से करवा सकते हैं। आदेश जारी होने के बाद दो महीने के भीतर सीआईपी करवा लिया जाना चाहिए। जो संस्थान इन निदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसमें अनुमोदन वापस लिया जाना / भर्ती की संख्या में कटौती करना या फिर नए पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किए जाने से इनकार किया जाना शामिल होगा।

समुद्रकर्मी / हितधारी की प्रतिक्रिया :

समुद्री वाणिज्य विभाग को बहुत-बहुत धन्यवाद एक ही दिन में डीसीई मिल गया।

शिव राजन प्रवीण कनकालयम टिकट नं. 328304

इमर्शन सूट और एन्टीत एक्सेपोजर सूट आवधिक जांच की आवश्यकता

इमर्शन या सर्वाइवल सूट एक विशेष प्रकार का बॉटर प्रूफ ड्राई सूट होता है जिस पहनने से बचाव होता है। निःसंदेह इसकी पर्याप्तन देख रेख किए जाने की आवश्यकता होती है।



नौवहन महानिदेशालय में दिनांक 31.05.2017 को परिपत्र सं. एन्टीी/ एलएसए/ 01/2017 जारी किया जिसमें कहा गया है कि हर सूट की वायुदाब जांच हर तीन साल के भीतर की जानी चाहिए और 10 साल के बाद यह जांच एक साल छोड़कर की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूट पर्याप्त रूप से मजबूत हैं और इनकी सिलाई यथापेक्षित रूप से बरकरार है।

यह वायुदाब जांच इनमें से किसी एक द्वारा की जाएगी (ए) भारत में स्थित नौमनि अनुमोदित ऐसा लाइफ राफ्ट सर्विस स्टेशन जिसके पास पर्याप्ती सुविधाएं हों या (बी) भारत के बाहर कोई आईएसीएस श्रेणी का अनुमोदित सर्विस स्टेशन या (सी) उक्त परिपत्र में दिए अनुसार पोतस्थ कार्मिक।

महीन अयस्कै / संकेद्रित कार्गो और समरूपी कार्गो- 100% पीएससी / एफएसआई की अपेक्षा से छूट

महीन अयस्कन / संकेद्रित अयस्कों और समरूपी कार्गो की लदाई वाले सभी जलयानों के 100 प्रतिशत पीएससी / ध्वज राष्ट्रा कार्यान्वयन निरीक्षण की अपेक्षा से दिनांक 01.06.2017 के एनटी / इंजीनियरिंग परिपत्र सं. 2/2017 के माध्यम से छूट प्रदान की गई। तथापि, पीएससी / एफएसआई को नौवहन महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वित नियमित पीएससी / एफएसआई व्यवस्था के भा के रूप में किया जाएगा।



इसके अलावा, वापोप सूचना सं. 9/2010 के अनुसार 'ए' श्रेणी के कार्गो के उपरांत लादने/ ले जाने से पहले संबंधित समुद्री वाणिज्य विभाग से निकासी अनुमति / अनुमोदन प्राप्ति करने की अपेक्षा से भी छूट प्रदान कर दी गई है।

समुद्रकर्मी / हितधारी की प्रतिक्रिया :

वैबसाइट पर ये बड़े कमाल की चीज है ... मैंने अपना सीडीसी बदलवाने के लिए आवेदन किया था और जब तक ये बदल नहीं गया तब तक मुझे अपने हर सवाल का जवाब तुरंत मिला। वाकई यह बहुत ही मददगार साबित हुआ है और समुद्रकर्मी को उन चिंताओं से मुक्ति मिल गई है जिनकी वजह से वह परेशान रहा करता था। आपका सबका धन्यवाद।

नितिन बी. नायर, टिकट नं. 377596

समुद्रीय श्रम कन्वेंशन, 2006 प्रशिक्षणार्थियों तथा कैडेटों के लिए प्रयोज्यता

नौमनि ने दिनांक 02.06.2017 की अपनी वापोप सूचना सं. 4/2017 के माध्यम से यह स्पष्ट किया था कि प्रशिक्षणार्थी और जलयानों पर नियोजित / कार्यरत कैडेटों पर समुद्रीय श्रम कन्वेंशन, 2006 के प्रावधान, जिस तरह से वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रीय श्रम) नियम, 2016 में दिए गए हैं वे उसी तरह से अन्य समुद्रकर्मियों की तरह उन पर लागू होंगे। इस संबंध में भारतीय पोत स्वामियों की ओर से अभ्यागवेदन देकर अनुरोध किया गया है कि समुद्रीय श्रम कन्वेंशन, 2006 के प्रावधानों से छूट प्रदान की जाए।



नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार ने इस विषयवस्तु पर हितधारियों के साथ व्यासपक बातचीत की और समुद्रीय राष्ट्रों के संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानों का हवाला भी दिया। तथापि, इस उपयुक्त नहीं पाया गया।

गोवा में दिनांक 08 और 09 जून, 2017 को अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण क्षतिपूर्ति तथा दायित्व व्यवस्था पर कार्यशाला

डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे, नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार के मार्गदर्शन में गोवा में 8 और 9 जून, 2017 को विवान्टाश बार्ड ताज पणजी में अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण क्षतिपूर्ति [आईओपीसी] व्यवस्था पर एक कार्यशाला का आयोजन नौवहन महानिदेशालय ने किया।



तेल के छलकने की वजह से वित्तीय नुकसान तो होता ही है साथ ही संपत्ति के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी होता है और मुख्य रूप से इसके कारण स्थातनीय मात्स्यिकी तथा पर्यटन उद्योग को क्षति पहुँचती है। सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लिए जाने के बाद भी सफाई का कार्य न सिर्फ चुनौती भरा बल्कि महंगा भी पड़ता है। तेल छलकने की वजह से जिन्हें नुकसान पहुँचता है वे क्षतिपूर्ति के पात्र होते हैं। हालाँकि तेल के छलकने के कारण हुई हानि हेतु नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रयोजनीय कानूनी व्यवस्था पर आधारित होगा। कार्यशाला में इसके प्रतिभागियों को यह अवसर प्रदान किया गया कि वे अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण क्षतिपूर्ति व्यवस्था का विहंगावलोकन करें और यह जानें कि दावा प्रक्रिया सहित संभावित रूप से क्षतिग्रस्त लोगों हेतु यह कैसे कार्य करती है।



इस कार्यशाला का आयोजन आईयूपीसी में थी, इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ पी एण्ड आई एसोसिएशनों और अंतरराष्ट्रीय टैंकर स्वाडमी प्रदूषण फेडरेशन (आईटीओपीएफ) के सहयोग से किया गया था।



8 जून को विशेष रूप से पोत परिवहन मंत्रालय, नौवहन निदेशालय और समुद्रीय वाणिज्य विभागों के अधिकारियों का आधे दिन का सत्र आयोजित किया गया था। इससे आईओपीसी निधियों, अंतरराष्ट्रीय ग्रुप ऑफ पी एंड आई एसोसिएशनों और अंतरराष्ट्रीय टैंकर स्वाीमी प्रदूषण फेडरेशन (आईटीओपीएफ) के शिष्ट मंडलों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने के लिए एक मंच मिला।

प्रमुख पत्तमनों, छोटे पत्तचनों, राज्य समुद्रीय मंडलों, मात्स्यिकी विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडलों निजी और सार्वजनिक तेल कंपनियों और बीमा कंपनियों के अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारियों सहित 160 प्रतिभागियों द्वारा 9 जून को आयोजित पूरे दिन की कार्यशाला में भाग लिया गया। इस कार्यशाला में महत्वपूर्ण जानकारी दिए जाने के लिए इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।



नौवहन महानिदेशालय ने दो बैठों में गैर तकनीकी (प्रशासनिक) मामलों के नए रंगरूटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया; (i) इसका आयोजन 12 से 24 जून, 2017 और (ii) 27 जून से 9 जुलाई, 2017 को पूना स्थित यशवंतराव चव्हाण अकेडमी ऑफ डिवैल्पमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यशदा) में किया गया। इस प्रशिक्षण का लक्ष्य उनके प्रोफेशनल कार्य - कौशल तथा कार्य की गुणवत्ता तथा संतोषप्रदता में वृद्धि लाना है और इसका लक्ष्य संगठनात्मक विकास तथा इसकी अपनी दृष्टि की दिशा में सफलता प्राप्त करना है।

वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक

16.12.2016 को वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016 लोकसभा में लाया गया जिसे विभाग संबंधी परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा जांचा और इस पर विचार किया जा रहा है। माननीय सांसद श्री मुकुल राय की अध्यक्षता में इस समिति ने 12.05.2017 को सचिव (नौवहन), भारत सरकार और नौमनि, भारत सरकार के विचार सुने। समिति द्वारा तमाम प्रश्न पूछे गए और बातें सामने लाई गईं और नौमनि ने उनका भी जवाब दिया।

इसके अलावा जून, 2017 मास में समिति की तीन और बैठके अहमदाबाद, मुंबई और कोचीन में की जाएंगी ताकि उक्त विधेयक पर हितधारियों और पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के विचार सुने जा सकें।

समिति अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी।

भारतीय ध्वज जलयानों के निरीक्षण (एफएसआई) की समीक्षा नौमनि ने की

दिनांक 18.06.2017 की वाणिज्यपोत परिवहन की सूचना सं.4/2017 के माध्यम से करीब 4 वर्ष के उपरांत नौवहन महानिदेशक ने अपने ध्वज राष्ट्र निरीक्षण (एफएसआई) की समीक्षा की।



इस समीक्षा की पृष्ठभूमि यह है कि वर्ष 2015 और 2016 कैलेंडर वर्ष के लिए एफएसआई और पत्तन राष्ट्र निरीक्षण के आंकड़ों से पता चला है कि 25 साल से कम आयु वाले और खास तौर से 15 साल से कम आयु वाले पोतों को बड़ी संख्या में रोका गया है। 25 साल से कम आयु वाले भारतीय ध्वज जलयानों की सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी स्थिति के बारे में इस वजह से चिंता हुई।

इस सूचना की कुछ विशेषताएं हैं:

- ❖ यह इस सूचना के जारी होने की तारीख से नदी समुद्र जलयानों और भारतीय तटवर्ती जलयानों सहित सभी जलयानों पर लागू होगा;
- ❖ ध्वज राष्ट्र निरीक्षणों की सारणी

क्र.सं.	पोत का प्रकार और आयु	ध्वज राष्ट्र निरीक्षणों की बारंबारता
1	यात्री पोत	प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में यात्री पोत सुरक्षा सर्वेक्षण के 3 महीने बाद किंतु इसकी तारीख समाप्त होने से 3 महीने पहले.
2	कार्गो पोत (0-5 वर्ष की आयु)	पहले पूर्ण अंतरवर्ती सांविधिक सर्वेक्षणों के पूरा होने के बाद 1 से 3 महीने के बीच एक निरीक्षण.
3	कार्गो पोत (5-15 वर्ष की आयु)	2 साल में एक बार यानी प्रत्येक 1 वर्ष के अंतर से वार्षिक / अंतरवर्ती / नवीकरण यथा स्थिति सांविधिक सर्वेक्षण के पूरा के बाद 1 से 3 महीने के बीच.

4	कार्गो पोत (15 वर्ष से अधिक आयु)	हर वर्ष वार्षिक / अंतरवर्ती / नवीकरण यथा स्थिति सांविधिक सर्वेक्षण के पूरा के बाद 1 से 3 महीने के बीच.
---	----------------------------------	--

- ❖ तय न किए गए ध्वजज राष्ट्र निरीक्षण : वर्तमान में अचानक निरीक्षण द्वारा एफएसआई किए जाने की व्यतवस्थाव और इसकी सूचना दिया जाना यथावत जारी रहेगा.
- ❖ ध्वनज राष्ट्र कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली (एफएससीआईएस) :
 - ए) हितधारियों के लाभार्थ भारत में पंजीकृत सभी पोतों के लिए नौमनि ने वेब आधारित केन्द्रीकृत कंप्यूटर सूचना प्रणाली बना रखी है
 - बी) नौवहन कंपनियों, मान्यतता संगठनों (आरओ) और सवावि से अपेक्षा है कि वे 2 कार्य दिवसों के भीतर इस डाटाबेस में सामान्य परीक्षा और एफएसआई की निरीक्षण रिपोर्टें अपलोड कर दें;
 - सी) यह सुनिश्चित करना कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि निश्चित अवधि के भीतर संबंधित आरओ द्वारा एफएससीआईएस पर सामान्य परीक्षा आद्यक्षर और त्रुटि सुधार रिपोर्टें अपलोड कर दी जाएं
- ❖ सत्यापन तथा अनुवीक्षण
 - ए) इस सूचना का अनुपालन कंपनी के वार्षिक डीओसी लेखा परीक्षण के दौरान सत्यापित किया जाएगा;
 - बी) कमियों को 1 मास की अवधि में पूरा कर लिया जाए;
 - सी) एफएसआई के लिए आवेदन की प्रक्रिया तथा एसओपी नौमनि की वैबसाइट पर उपलब्धि है

समुद्रकर्मि/ हितधारी की प्रतिक्रिया

वैबसाइट बहुत ही बढ़िया है इससे हर किसी का काम घट गया है.

श्री दिव्य भान सिंह उदय राजावत. टिकट नं. 949975

‘नाविक’ दिवस’ समारोह

राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह (केन्द्रीय) दिनांक 25 जून, 2017 को मुंबई में आयोजित किया गया। ‘हार्टफुलनेस मास्टर क्लास’ ध्यादन कार्यक्रम का आयोजन श्री संजय भाटिया, भाप्रसे, चेयरमैन, मुंबई पत्तहन न्यास के मार्गदर्शन में के. आर. कामा इन्टीयोक्यूट बिल्डिंग, बम्बई समाचार, पोर्ट, मुंबई में किया गया।



मुख्या आयोजन, ‘समुद्रकर्मियों को पुरस्कार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम’ का आयोजन समुद्री प्रशिक्षण संस्थान, पवई, मुंबई में किया गया

श्री अमिताभ कुमार, भाराजे, अपर नौवहन महानिदेशक से मुख्य अतिथि का स्थादन ग्रहण कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस दिन शुरुआत एसटीसीडबल्यू कन्वेंशन पर मनीला में 2010 की कॉन्फ्रेंस द्वारा अंगीकृत संकल्प हुआ।



प्रयोजन यह है कि दुनिया भर के समुद्रकर्मियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार, विश्वा की अर्थव्यवस्था और समूचे सामाजिक ढांचे में उनकी अनूठी भूमिका को मान्यता प्रदान की जाए. नाविक दिवस का विषय, 'नाविक का बड़ा महत्व है' था.



डॉ. मालिनी वि. शंकर भाप्रसे, नौवहन महानिदेशक के मार्गदर्शन में भारतीय नौवहन एक्स पो का आयोजन 27 और 28 जून, 2017 को मंत्रालय में नाविक दिवस के अवसर पर किया गया. एक्सकपों का उद्घाटन श्री सुमित मलिक भाप्रसे, मुख्यो सचिव, महाराष्ट्र सरकार ने किया.



समुद्रकर्मों/ हितधारी की प्रतिक्रिया

ऑनलाइन बुकिंग सबके लिए बहुत बढ़िया है.

महेन्द्र यादव टिकट नं०689908



अप्रत्यक्ष कर संरचना के नए
युग का सूत्रपात- नौमनि
द्वारा जागरूकता कार्यक्रम

भारत के आर्थिक इतिहास में माल और सेवा कर (जीएसटी) आज तक का सबसे बड़ा सुधार है. इससे भारत में आर्थिक सुदृढ़ता की एक नई शुरुआत होगी. जीएसटी 1 जुलाई, 2017 से लागू किया जा रहा है.

आरंभ में नौमनि ने माल और सेवा कर (भारत) के बारे में जागरूकता पर एक भाषण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें नौवहन क्षेत्र में जीएसटी के लागू होने पर बल दिया गया इसका आयोजन 27 जून, 2017 को नौमनि मुंबई के सभाकक्ष में हुआ. श्री कमलेश दवे, सीए ने यह भाषण दिया और श्री आर एस अय्यर, सीए ने उनकी सहायता की. इस कार्यक्रम में नौमनि के अधिकारी, इन्सा , मासा, फोसमा के प्रतिनिधि और नौवहन उद्योग के अन्यत हितधारी शामिल थे. इस भाषण में अन्य, बातों के साथ-साथ आधारभूत संरचना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कराधान का स्थान, उद्योग पर प्रभाव के अंतर्गत इनकी मुख्यन विशेषताएं और मुख्य परिभाषाएं शामिल की गई, इसके बाद प्रश्नोत्तर का क्रम चला.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म 238 शताब्दी समारोह

भारत सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म 238 शताब्दी मना रही है। माननीय पोत परिवहन मंत्री महोदय ने इच्छा व्यक्त की है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नीचे दिया गया लोगो को शताब्दी समारोह के दौरान मंत्रालयों तथा संगठनों के सभी विज्ञापनों में प्रयोग किया जाए।



क्लास 2 परीक्षा के लिए मुंबई सवावि में किए गए मूल्यांकन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसमें अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से अनुदेश दिए और क्लास 2 परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु किसी समस्या का सामना कर अभ्यर्थियों की मदद की। मुझे हैरानी हो रही थी कि इतने सारे लोग मूल्यांकन के लिए आए थे और अधिकारियों ने कार्य को इतनी तेजी से संपन्न किया कि सब का कागजी काम एक ही दिन में पूरा हो गया। पूरी टीम ने भरपूर कौशल के साथ कार्य किया। ऑनलाइन बुकिंग की वजह से परीक्षा का शुल्क देना बहुत आसान हो गया है। जहां तक परीक्षाओं का प्रश्नक है नौवहन महानिदेशालय का भवन बड़ा ही आकर्षक और सुविधा से सुसंपन्न है। मौखिक परीक्षा देने से पहले बैठने के लिए जगह बहुत ही अच्छी है तथा साफ-सुथ शौचालय, पीने का ठंडा पानी और प्रतीक्षा के लिए वातानुकूलित जगह जैसी सुविधाएं बड़ी अच्छी लगी। और मैं मौखिक परीक्षा देते समय बहुत ही सहज था। कुल मिलाकर 2012-13 में मैंने जब क्लास 4 की परीक्षाएं दी थी तब से आज मैं आया अंतर मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का कारक रहा है। चीजें बड़ी से बदली है। इतने सुखद अनुभव के लिए धन्यवाद

जयंत सिंह नेगी टिकट नं. 238581

नाविक का अर्थ

वाणिज्य पोत परिवहन
(समुद्रीय श्रम) नियम, 2016 में
दिए अनुसार समुद्रीय श्रम
कन्वेंशन के प्रावधानों की दृष्टि
से समुद्रकर्मों का अर्थ है :



“कोई ऐसा व्यक्ति जो समुद्रगामी पोत पर किसी क्षमता में नौकरी करता हो या कार्य पर लगाया गया हो या कार्य करता हो किंतु इनमें ये लोग शामिल नहीं हैं:

- i) युद्ध पोत में कोई व्यक्ति किसी क्षमता में पोत पर नौकरी कर रहा हो या कार्य पर लगाया गया हो या कार्य करता हो या
- ii) कोई सरकारी पोत जो कि सैनिक या वाणिज्येतर प्रयोजनों से चलाया जाता हो”

समुद्रकर्मों/ हितधारी की प्रतिक्रिया

मेरी ओर से कमाल की इस मददगार ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद.

कृष्णओ होडा टिकट सं68773

	शिकायतों/ प्रश्नों के समाधान के लिए समुद्रकर्मियों और हितधारियों हेतु सुविधा
---	---

सभी समुद्रकर्मियों / हितधारी निम्नोक्त संबंधित अपने प्रश्न/ समस्याएं भेज सकते हैं

(1) ई-गवर्नेंस के मामले :

ई-मेल आईडी	फोन नं.	एक्स्टेंड
egovernance-dgs@nic.in	022-25752040/41/42/43	282/283

(2) अन्य मामलों के लिए:

(i) निदेशालय को ई-मेल (helpdesk-dgs@gov.in) के माध्यम से प्रश्न / समस्याओं का समाधान हेतु भेजे जाने के लिए सुविधा है

(ii) एक ऑनलाइन सहवर्ती फीडबैक शिकायत समाधान प्रणाली बनाई गई है और यह जून, 2016 से सक्रिय है. यह बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन सेवा है जिससे शिकायतों का समाधान किया जाता है. समुद्रकर्मियों/ हितधारियों को भी सेवाओं को अंक देने का विकल्प दिया गया है. आज तक 2318 (30.06.2017 की स्थिति के अनुसार) प्रश्नों का उपयुक्त रूप से जवाब दिया गया है/ समाधान किया गया है. समुद्रकर्मियों / हितधारी इस प्रणाली का प्रयोग कारगर और परिच्छेद 21 के अंतर्गत लिखे अनुसार ई-मेल के वैकल्पिक तरीके रूप में अपना रहे हैं. ऑनलाइन प्रणाली के लिए ये कदम निम्नावत् उठाए जाएंगे:

Log in >www.dgshipping.gov.in>feedback>feedbackcenter> helptopic.

(iii) हेल्पडेस्क की ई-मेल आईडी और टेलीफोन नं. नीचे दिए गए हैं :

ई-मेल आईडी	फोन नं.	एक्स्टेंशन
helpdesk-dgs@gov.in	022-25752040/41/42/43	236

एसएमसी / डीओसी / डीडीओसी एक नजर में

तिमाही के दौरान जारी किए गए एसएमसी/ डीओसी/ डीडीओसी का विवरण एक नजर में

जारी किए गए एसएमसी/ डीओसी/ डीडीओसी

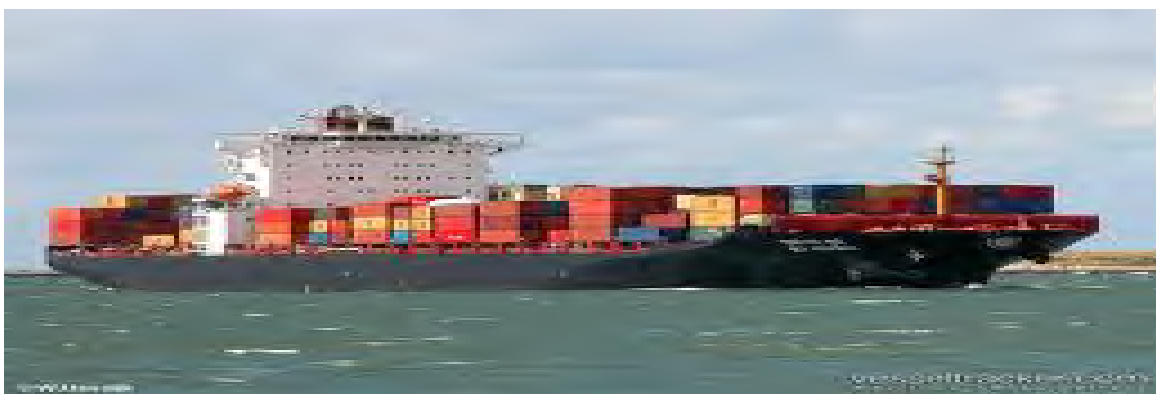
विषय	अप्रैल, 17	मई, 17	जून, 17	कुल
एसएमसी	09	12	15	36
डीओसी	04	05	11	20
डीडीओसी	01	02	01	04

समुद्रकर्मियों/ हितधारी की प्रतिक्रिया

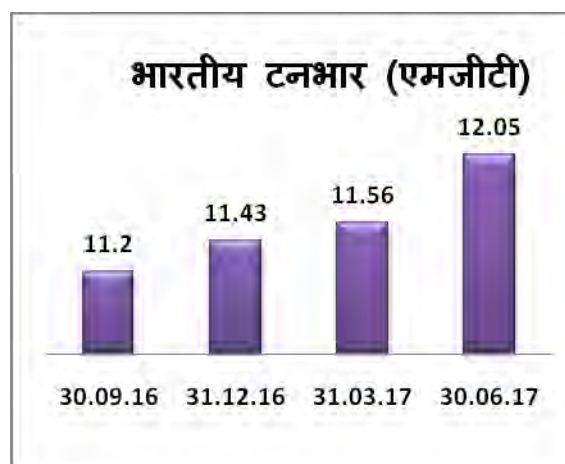
परीक्षाएं बहुत अच्छी तरह से ली जाती हैं, सीट बुक करना आदि सभी कुछ बहुत अच्छा है.

अंगद सिंह टिकट नं. 208673

भारतीय नौवहन टनभार



भारतीय पोतों में भारतीय नियंत्रण वाले पोत शामिल हैं और स्थिति नीचे दिए गए ग्राफ में मिलियन सकल टनभार के रूप में टनभार स्थिति दर्शाई गई है:



सवावि, चेन्नई का धन्यवाद कि एक ही दिन में अनुमोदन और अभ्यर्थी को डीसीई मिल भी गया.
प्रवीण टिकट नं.. 894080

आईएमओ प्रतिभागिता:

भारत आईएमओ का एक सक्रिय सदस्य है गत तिमाही के दौरान निम्नोक्त अधिकारियों ने आईएमओ लंदन, सिंगापुर, लिश्टेन्टीई मन् और न्यूयार्क में आयोजित सत्रों / बैठकों में भाग लिया



1.	पोत उपकरण और प्रणाली(एसईएस) पर उप समिति के चौथे सत्र में दिनांक 20.04.17 से 24.04.2017 तक श्री नेबू ओमेन पोत सर्वेक्षक सवावि, मुंबई उपस्थित रहे ;
2.	दिनांक 24.04.17 से 28.04.2017 तक आईओपीसी फंड मीटिंग में कप्तान जयाकुमार, उप नॉटिकल सलाहकार और श्री आस मोहम्मद उमनि (प्र) ने भाग लिया;
3.	दिनांक 26.04.17 से 28.04.2017 तक श्री अमिताभ कुमार अपर महानिदेशक ने आईएमओ की विधिक समिति के 104थे सत्र में भाग लिया;
4.	दिनांक 13.05.17 से 17.05.2017 तक श्री सुरेश कुमार आरएम, मुख्य पोत सर्वेक्षक द्वारा आईएमओ सदस्यक राष्ट्रे लेखा परीक्षा के अंतर्गत किरीबाती की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा का नामांकन में उपस्थित रहे;
5.	दिनांक 29.05.17 से 02.06.2017 तक ईएफटीए - भारत बातचीत का 16वां राउंड, मेलबन में श्री आस मोहम्म द उमनि (प्र) उपस्थित रहे
6.	दिनांक 05.06.17 से 09.06.2017 तक श्री ए.बी. दत्ताप, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक एसडीजी-4 के कार्यान्वहन में समर्थन की यूएन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे
7.	दिनांक 23.06.2017 को डॉ. मालिनी वि. शंकर, भाप्रसे, नौवहन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार ने फेयर ट्रीटमेंट ऑफ सीफेयरर्स पर कार्यशाला में भाग लिया.

2) पदोन्नति:

1.कप्तान एस.आई अबुल कलाम आज़ाद, नॉटिकल सर्वेक्षक को दिनांक 16.06.2017 को उप नॉटिकल सलाहकार के पद पर पदोन्नत कर सवावि, मुंबई में तैनात किया गया है.

3) पेंशन पेपर / केस: निम्नोक्तों पेपर पेंशन/ केस तैयार कर पीएओ (नौ)

मुंबई एवं कोलकाता तथा आईएमयू परिसर, मुंबई तथा कोलकाता को भेज दिए गए हैं.

- 1.श्री राजू प्रसार कलीनर हैंड आईएमयू, कोलकाता.
- 2.श्री सुप्रिय दास, स्टोयरकीपर आईएमयू कोलकाता.
3. श्री वी.ए. ठोरट, आईएमयू, मुंबई.

4. श्री दिलीप कुमार, सिकंदर, क्लीयर हैंड, आईएमयू कोलकाता.
5. श्री टी. के. गांगुली, वर्कशाप अटेंडेंट, आईएमयू कोलकाता.
6. श्री ए. एच. बैकर, एमटीएस (चपरासी), आईएमयू मुंबई.
7. श्री एस.एस. देसाई, लेखापाल आईएमयू मुंबई.
8. श्री माइकल कोली, नाविक, आईएमयू मुंबई.
9. श्री तपन भट्टाचार्य, आईएमयू कोलकाता.
10. ग्रुप बी और सी के पेंशन मामलों के निपटान का कार्यान्वयन प्रत्येक ग्रुप में केश भविष्य. पेंशनर पोर्टल2 के माध्यम से प्रक्रियागत हैं.

4) नई नियुक्ति :

1. कसाईन एस. मुखोपाध्याय, नॉटिकल सर्वेक्षक 10.04.2017 से ;
2. श्री संदीप अवस्थी, सहायक नौवहन महानिदेशक 19.04.2017 से;
3. कसासन पूरण चंद मीणा, नॉटिकल सर्वेक्षक 17.05.2017 से.

5) स्थानांतरण और तैनाती :

- (I) कसांन मोहित कुमार बहल, सवावि, मंगलौर से नौमनि, मुंबई 04.04.2017 से .
- (II) कसांन तपेश घोष, विशाखापट्टनम से सवावि, चेन्नई 04.04.2017 से.
- (III) कसापन नितिन मुकेश, सवावि, कोलकाता से सवावि, मुंबई 17.04.2017 से .

6) एमसीपी:

- (I) नौमनि के वर्ग 'ख' अधिकारी और वर्ग 'घ' कर्मचारियों को एमएसीपी दी गई – कुल 12.
- (II) एमपीएसओ के वर्ग 'क' अधिकारियों को एमएसीपी दी गई कुल-2

7) ऑनलाइन मांग : नौमनि और अधीनस्था कार्यालयों के वर्ग 'ग' कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को ऑनलाइन मांग भेजी गई-कुल 87 पद

8) मूल विभाग में वापस जाना : डॉ. अमोल बी. कीर्तने, भारासे, उमनि, प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के उपरांत अपने मूल कार्यालय में चले गए.

9) सेवा निवृत्ति : कसा न एस. के. शुक्लार, प्रधान अधिकारी सवावि, कांडला, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर सरकारी सेवा से दिनांक 30.06.2017 को सेवानिवृत्तक हो गए.

राजभाषा हिंदी



नौवहन महानिदेशालय

दिनांक 27.04.2017 को नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार डॉ. मालिनी वि. शंकर की अध्यक्षता में संपन्न 7 राजभाषा कार्यान्वयेन समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा यह आदेश दिया गया था कि सातवें समुद्रकर्म दिवस के अवसर पर विभिन्ना समुद्रकर्मियों तथा नौवहन कंपनियों आदि के साथ हिंदी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का अयोजन किया जाए. जिससे निदेशालय के साथ-साथ समुद्री जगत में भी हिंदी के प्रति रुझान बढ़े. उक्त आ के अनुसरण में निम्नरलिखित कार्यक्रम किए गए :

1. दिनांक 25.06.2017 को सुबह 9 बजे से 10 तक कामा हॉल लायन गेट के सामने मुंबई पत्तन न्या स के अध्यक्ष, श्री संजय भाटिया, भा.प्र.से. के मार्गदर्शन में एसोसिएशनों सहित समुद्रीय जगत के गण्यनमान व्यक्तियों के साथ-साथ समुद्रकर्मियों को ध्यान-योग का अभ्यास करवाया गया.



2. हिंदी नाटक, गायन आदि विभिन्ने कार्यक्रमों का मंचन तथा प्रस्तुतियां दिनांक 25.06.2017 को एमटीआई, एससीआई, पवई के हॉल में मुख्यन समारोह के दौरान धूमधाम के साथ आयोजित की गई.

3. इनमें भाग लेने वाले समुद्रकर्मियों को मेमेंटों प्रदान किए गए. भविष्यध में नकद पुरस्कार आदि विधिवत् दिए जाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी.
4. इस नाविक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपर नौवहन महानिदेशक श्री अमिताभ कुमार, भा.रा.से. पधारे. उक्त अवसर पर प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई उपस्थित थे तथा नौवहन जगत की एसोसिएशनों सहित तमाम गण्यजमान्यव लोग और एमटीआई के प्रिंसिपल, कप्तान फिलिप मैथ्यू ज्ञ सहित विभिन्न समुद्रकर्म संस्थानों के शिक्षक, प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षणार्थियों से दर्शक दीर्घा खचाखच भरी हुई थी.



5. समूचे नौवहन जगत सहित विभिन्नी नौवहन कंपनियों तथा नौवहन संबंधी प्रशिक्षण संस्थाओं ने भी अंग्रेजी की लीक से हटकर हिंदी में कार्यक्रम आयोजित किए जाने की दिशा में बढ-चढ कर उत्साह दिखाया.
6. इस प्रकार से नाविक दिवस के उपलक्ष्य में किए गए आयोजन सफलतापूर्वक हिंदी में कर संघ की राजभाषा के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि के क्रम में एक और अध्याय जोड़ा गया.

7. उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी प्रस्तुतियां तथा यथासंभव वक्तव्य हिंदी में ही दिए गए. एमसी (मास्टर ऑफ सेरेमनी) की भूमिका निभाते हुए निदेशालय के श्री विमलेन्द्र आर्भदौरिया ने उक्त दोनों कार्यक्रमों का संचालन एमसी (मास्टर ऑफ सेरेमनी) की भूमिका निभाते हुए निदेशालय के श्री विमलेन्द्र भदौरिया ने उक्त दोनों कार्यक्रमों का संचालन हिंदी में किया.



2) इस तिमाही में सहायक निदेशक (रा.भा.) द्वारा नामतः प्रशिक्षण , कार्मिक, नॉटिकल, समन्वय एवं नौवास्तु अनुभाग का क्रमशः दिनांक 19.06.17, 20.06.17, 21.06.17, 22.06.17 एवं 23.06.17 को राजभाषा हिंदी से संबंधित निरीक्षण किया गया .

3) नगर राजभाषा कार्यान्वायन समिति , उत्तर मुंबई (कार्यालय) की बैठक दिनांक 29 मई , 2017 को पूर्वाह्न 11.30 बजे सीप्ल सेज़ में विकास आयुक्त 6 सीप्ल (की अध्यक्षता में आयोजित हुई. इस प्रथम छमाही बैठक में इस महानिदेशालय के उप नौवहन महानिदेशक (प्रशासन) के साथ सहायक निदेशक (राभा) द्वारा भाग लिया गया. इस बैठक में राजभाषा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई.

4) नौवहन महानिदेशालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव , भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 27/04/2017 को आयोजित की गई. इस बैठक में निदेशालय के सभी अनुभाग और अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की गई.

5) नौवहन महानिदेशक द्वारा निदेशालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने एवं कंप्यूटर पर अधिकाधिक कार्य यूनीकोड और इससे संबंधित टूल्स के माध्यम से किए जाने के बारे में कार्यशाला को आयोजित किए जाने संबंधी आदेश का पालन करते हुए निदेशालय के सभी कार्मिकों के लिए कंप्यूटर एवं इससे संबंधित टूल्स की जानकारी देने के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन दिनांक 29.06.2017 को किया गया. इस विशेष कार्यशाला में हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक, श्री अनंत श्रीमाली द्वारा उक्त के संबंध में जानकारी प्रदान की गई.

.....

क्षेत्रीय कार्यालयों में गतिविधियां



समुद्री वाणिज्य विभाग (सवावि), चेन्नैनई

पतन्ना राष्ट्रा नियंत्रण/ ध्वाज राष्ट्रा कार्यान्वयन के अंतर्गत 10 निरीक्षण किए गए. इसी तरह से तिमाही के दौरान 17 जलयानों का सर्वेक्षण किया गया. तिमाही के दौरान 3 प्रशिक्षण संस्थानों को अनुमोदन दिए जाने के लिए निरीक्षण किया गया. इंजीनियरिंग परीक्षाओं में 626 अभ्यर्थी बैठे तो नॉटिकल परीक्षाओं में 263 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. तिमाही के दौरान 1447 प्रमाणपत्र जारी किए गए जिनमें सीओसी को मान्यता दिया जाना, सीओसी और डीसीई आदि शामिल थे. गतिविधियों का विवरण निम्ना नुसार हैं :

- ❖ 54वें राष्ट्रीय समुद्रीय दिवस समारोह के भाग के रूप में विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि प्रेस कांफ्रेंस, सेमिनार, मार्च पास्ट, वरिष्ठ समुद्रकर्मियों को सम्मानित किया जाना आदि 3.04.2017 से 5.04.2017 तक आयोजित किए गए;
- ❖ स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में सवावि, चेन्नई और एसडब्ल्यूकि ओ/ एसईओ/ एसओ, चेन्नई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिनांक 03.04.2017 को कार्यालय परिसर के सफाई का कार्य किया साथ ही 8.04.2017 (शनिवार) को पूरे कार्यालय परिसर जैसे कि बरामदे, सीढ़िया कार्य करने की जगह और पार्किंग की जगह के रास्ते प्रयोग में न लाए गए सामान का निपटान, फर्नीचर, उपकरण आदि सहित एंकरगेट बिल्डिंग के बाहर पूरे कार्यालय परिसर की सफाई के कार्य किए गए.

- ❖ 19.04.2017 को पीएससी/ एफ एसआई निरीक्षण से संबंधित मामलों पर सवावि, चेन्नई के अधिकारियों के साथ नौमनि, मुंबई द्वारा एक वीडियो कॉफ्रेंसिंग की गई.
- ❖ 8-9 जून, 2017 को अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण क्षतिपूर्ति और उत्तीरदायित्वक व्यवस्था पर विवांटा बाई ताज पणजी, गोवा में आयोजित कार्यशाला में श्री एस. बारिक, प्रधान अधिकारी, सवावि, चेन्नई और कप्तान तपेश घोष, नॉटिकल सर्वेक्षक, सवावि, चेन्नई ने भाग लिया.
- ❖ सवावि, चेन्नई ने 21.06.2017 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मानाया गया . योग के महत्व पर एक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया.
- ❖ 22.06.2017 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया. अपने रोजाना के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करने के लिए सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रोत्साजित किया गया.

समुद्रकमी/ हितधारी की प्रतिक्रिया

अनुभव बहुत अच्छा रहा; परीक्षा हॉल की व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी थीं. परिणाम समय पर आ गया. कर्मचारी बहुत ही मददगार थे.

विन्देश्वरी तिवारी टिकट नं० 80714